(2013) 6 एस.सी.आर. 230

एस. मल्ला रेड्डी

बनाम

मैं. फ्यूचर बिल्डर्स कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी व अन्य

(सिविल अपील नं. 3914/2013)

अप्रैल 18, 2013

(पी. सताशिवम और एम.वाई. इकबाल, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिताए 1908 - आ. 6, नि. 16 और 17 और आ. 8 नि. 9 - स्वामित्व की घोषणा और शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा - प्रतिवादी-अपीलकर्ता के द्वारा आ. 6 नि. 17 में दायर याचिका के द्वारा लिखित बयान में संशोधन की मांग - चुनौती - अवधारितः प्रतिवादियों द्वारा आ. 6 नि. 17 में मांगी गई राहत को पूर्व की आ. 6 नि. 16 व आ. 8 नि. 9 की याचिकाओं को विस्तृत रूप से निपटाते हुए खारिज किया गया - मुकदमे की सुनवाई पूर्व से ही शुरू हो गई थी और कुछ गवाहों का परीक्षण भी हो चुका था, तो ऐसे में प्रतिवादियों के द्वारा आ. 6 नि. 17 की याचिका लगभग 13 साल बाद पेश करना पूरी तरह से गलत था - उसी राहत के लिए पुनः प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है- न्यायालय का दुरूपयोग

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आ. 6, नि. 16 और आ. 6 नि. 17 - के बीच में अंतर - विवेचना की गई।

वादी - प्रत्यर्थी सोसायटी ने संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा दायर की और प्रतिवादी-अपीलार्थी को कब्जे में हस्तक्षेप से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दायर की। प्रतिवादी मुकदमे पर न्यायालय से डिक्री के लिए वादी के दावे को स्वीकार करने का लिखित कथन पेश करते हैं। बाद में प्रतिवादियों ने आदेश 6 नियम 16 सी.पी.सी. के तहत याचिका प्रस्तुत करते हुए अनुतोष चाहा कि पूर्व के लिखित कथनों को रद्द कर दिया क्योंकि वह उनके हितों के विरूद्ध था। दूसरी याचिका प्रतिवादियों के द्वारा आदेश 8 नियम 9 और आदेश 6 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से विस्तृत रूप से लिखित कथन पेश किए जाने हेतु अनुमति के लिए पेश की। विचारण न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को यह अवधारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी-अपीलार्थी को दावे में लिखित कथन को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत उन्होंने वादी-सोसायटी के दावे को स्वीकार कर लिया था। प्रतिवादी-अपीलार्थी ने इस आदेश को चुनौती दी परंतु इस न्यायालय तक उनकी मांग खारिज हो गई। इसके बाद, प्रतिवादीगण-अपीलार्थी ने आ. 6 नि. 17 सी.पी.सी. के अंतर्गत लिखित कथनों में संशोधन की मांग चाहते हुए याचिका प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय के द्वारा संशोधित याचिका स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध वादी सोसायटी ने पुनरीक्षण याचिका

प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की और विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द किया, और जिस पर यह अपील प्रस्तुत हुई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए-

अवधारित कियाः 1. आ. 6 नि. 16 सी.पी.सी. दलीलों के संशोधन या खारिज करने से संबंधित है जिसे पक्षकार अपने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों में किए जाने की इच्छा रखते हैं। दूसरे शब्दों में, वादी या प्रतिवादी प्रतिद्वंद्वी की दलीलों को इस आधार पर खारिज करने के लिए कह सकता है कि बताई गई दलीलें अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या परेशान करने वाली है। यह नियम एक्स डेबिटो जस्टिटिया के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी दलील में दर्शित होने वाले अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ, परेशान करने वाले या जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों, मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में देरी कर सकने वाले मामले को खारिज कर सकता है। दूसरी ओर आ. 6 नि. 17 सी.पी.सी. न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी पक्षकार को उसकी याचिका में बदलाव या संशोधन की अनुमति दे सकता है और ऐसे प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उक्त नियम में दर्शित कुछ शर्तों के अधीन याचिका में संशोधन करने की अनमति दे सकता है।

2. इस मामले में प्रतिवादी-अपीलार्थी ने यद्यपि याचिका में अपनी दलीलों जो कि लिखित कथन है, को रद्द किए जाने की याचिका प्रस्तुत की है, याचिका को आ. 6 नि. 16 सी.पी.सी. का रूप दिया गया, लेकिन सार रूप में प्रार्थना पत्र को इस प्रकार से निपटाया गया है कि जैसे कि यह आ. 6 नि. 17 सी.पी.सी. के तहत हो, क्योंकि विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर चर्चा की और प्रतिवादी को लिखित कथन बदलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके तहत वादी-सोसायटी के दावे को स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित याचिका को खारिज करते हुए यह अवधारित किया कि प्रतिवादी-अपीलार्थी को दावे में प्रस्तुत अपने पूर्व के लिखित कथन को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत उन्होंने वादी-सोसायटी (प्रत्यर्थी) के दावे को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित सभी निर्णयों पर विचार किया कि क्या प्रतिवादीगण लिखित बयान में की गई अपनी स्वीकारोक्ति वापिस ले सकते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी-अपीलार्थी को आदेश 8 नियम 9 या आदेश 6 नियम 16 सी.पी.सी. का सहारा लेकर नए लिखित कथनों को प्रस्तुत कर पूर्व के लिखित कथनों में की गई स्वीकारोक्ति से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपरोक्त परिसर में लगभग 13 वर्षों के बाद आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रतिवादियों के द्वारा याचिका दायर करना जबकि मुकदमे की सुनवाई

पहले ही शुरू हो चुकी थी और कुछ गवाहों का परीक्षण भी हो गया था, पूरी तरह से गलत है। उच्च न्यायालय के जिस आदेश पर आपत्ति जताई गई है उसमें यह सही अवधारित किया है कि समान राहत के लिए दाखिल किए गए आगामी आवेदन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है। आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादियों द्वारा बाद की याचिकाओं में मांगी गई राहत को पूर्व की दो याचिकाएं जो कि आदेश 6 नियम 16 और आदेश 8 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था, में विस्तृत रूप से निपटाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण के द्वारा पेश की गई बाद की याचिकाएं जिन्हें कि आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का लेबल दिया गया था, पूरी तरह से गलत हैं और स्वीकार योग्य नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3914/2013.

ए. पी. उच्च न्यायालय, हैदराबाद की सी.आर.पी. नं. 5139/2007 के 28.12.2007 के निर्णय व आदेश से उत्पन्न

सिविल अपील नं. 3915 और 3916/2013

दुष्यंत ए. दवे, हुजेफा ए. अहमदी, एल. नागेश्वर राव, पी.एस. नरसिम्हा, एस. उदय कुमार सागर, बीना माधवन, अनंदिता पुजारी, आनंद कुमार कपूर (लाॅयर्स निट एंड कंपनी के लिए) वेनायगम बालन, एम.पी. शोरावाला, श्रीधर पोटाराजू, प्रभाकर, गैचांगपौ गैंगमई, अनंगा भट्टाचार्य, ए.

वेनायगम बालन, राधा श्याम जीना, जाॅन मैथ्यू उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

इस न्यायालय का यह निर्णय **एम.वाई. इकबाल जे.** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई.

2. प्रतिवादियों (यहां अपीलकर्ताओं) ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 28.12.2007 को चुनौती दी है, जिसके तहत वादी-प्रतिवादी (मैसर्स फ्यूचर बिल्डर्स कॉप सोसाइटी) द्वारा अनुच्छेद के तहत दायर की गई पुनरीक्षण याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 की अनुमति दी गई है और लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने वाले विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है।

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं।

4. वादी-प्रतिवादी मेसर्स. फ्यूचर बिल्डर्स को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (संक्षेप में "वादी सोसायटी") ने प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ वाद की अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति (संक्षेप में "मुकदमा संपत्ति") के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए

मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों को कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकें। वादी-सोसायटी का मामला यह है कि सोसायटी आंध्र प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण या खरीद करना और उसे रहने के लिए उपयुक्त बनाना है। सोसायटी की स्थापना प्रथम प्रतिवादी-एस सहित कई प्रवर्तकों द्वारा की गई थी। मल्ला रेड्डी (यहाँ अपीलकर्ता)। वादी का आगे का मामला यह है कि सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकरण के उद्देश्य से , रजिस्ट्रार को यह दिखाना आवश्यक था कि उन्होंने अपने सदस्यों के लाभ के लिए भूमि की खरीद के लिए एक समझौता किया है। यह आरोप लगाया गया था कि सोसायटी पंजीकृत होने से पहले, इसके प्रमोटरों ने मुकदमे की भूमि को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना और मालिक के साथ बातचीत की और माप और रुपये की राशि के बाद खरीद को प्रभावित करने के लिए पहले प्रतिवादी को काम सौंपा। उसे 10,000/- का भुगतान किया गया। पहले प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि उसने सोसायटी के मुख्य प्रमोटर के पक्ष में 8.3.1978 को एक समझौता निष्पादित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहमति थी कि पहला प्रतिवादी भूमि की माप कराएगा और कानूनी राय प्राप्त करेगा और भूमि मालिक को पैसे का भुगतान करेगा। यह सहमति हुई कि बिक्री विलेख पहले प्रतिवादी के नाम पर प्राप्त किया जाएगा और सोसायटी के लाभ के लिए उसके या उसके नामांकित

व्यक्ति के नाम पर पट्टा हस्तांतरित किया जाएगा। सोसायटी 28.08.1981 को पंजीकृत हुई थी और प्रतिवादी नंबर 1 ने दिनांक 02.01.1979 को एक बिक्री विलेख प्राप्त किया था और अपने और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 (यहाँ अपीलकर्ता) के नाम पर पट्टे का हस्तांतरण किया था, जो उसकी पत्नी और बेटे हैं। वाद की संपत्ति का सम्मान करते हुए, सोसायटी को कब्ज़ा दे दिया गया था और वे वादी-सोसायटी के नाम पर पट्टा सुरक्षित करने के लिए सहमत हुए थे। दिनांक 16.09.1981 को एक समझौता ज्ञापन भी निष्पादित किया गया था कि वादी भूमि को मालिक के रूप में रखेगा। वादी-सोसाइटी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी, कई अनुरोधों और मांगों के बावजूद, किसी न किसी बहाने से वाद संपत्ति के संबंध में पट्टा के हस्तांतरण को उसके नाम पर स्थगित कर रहे थे। इसलिए, मुकदमा किया गया।

5. बुलाए जाने पर, प्रतिवादी उपस्थित हुए और 19.01.1995 को एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया जिसमें वादी के दावे को स्वीकार करते हुए कहा गया कि मुकदमा दायर करने के बाद एक मध्यस्थता हुई जिसमें विवाद का निपटारा किया गया और तदनुसार, रुपये की राशि दी गई। उन्हें 1,00,000/- का भुगतान किया गया और फिर वे मुकदमे की संपत्ति के संबंध में वादी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरित करने के इच्छुक थे, जिसने पहले ही स्वामित्व हासिल कर लिया था। इसलिए, प्रतिवादियों ने न्यायालय से मुकदमे पर फैसला सुनाने की प्रार्थना की।

6. विवाद तब शुरू हुआ जब प्रतिवादियों ने लिखित बयान दाखिल करने और वादी के दावे को स्वीकार करने के बाद 1995 की आईए संख्या 2217, जिसे बाद में 2000 की आईए संख्या 162 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, में एक याचिका दायर की और जमीन पर अपने वकील बदलने की अनुमति मांगी। कि वे निर्देशों के विपरीत लिखित बयान दाखिल करके उनके हितों के लिए हानिकारक कार्य कर रहे हैं। उक्त याचिका पर वादी द्वारा आपत्ति की गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.02.2000 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने वकील बदलने की अनुमति दी। इसके बाद, प्रतिवादियों ने 28.02.2000 को नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 6 नियम 16 के तहत एक और याचिका दायर की, जो कि 2000 के आईए नंबर 415 के तहत लिखित बयान में दलीलों को हटाने या लिखित को मिटाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी गई थी। बयान और उन्हें एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देना। यह आरोप लगाया गया कि पूर्व में दायर लिखित बयान वादी द्वारा अपने वकील को दिए गए निर्देशों के विपरीत था। सीपीसी के आदेश 8 नियम 9 और आदेश 6 नियम 5 के तहत 2000 के IA नंबर 416 के प्रतिवादियों द्वारा एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें विस्तृत लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी गई थी। उन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कुछ और विकास हुए। पहले

प्रतिवादी के सबसे छोटे बेटे ने 2000 के एलए 1819 में एक याचिका दायर की और न्यायालय से उसे उन दो अंतरिम याचिकाओं में पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी, जिसे हालांकि अनुमति दी गई थी और उक्त बेटे को रिकॉर्ड पर लाया गया था।

7. विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद सामान्य आदेश दिनांक 04.01.2002 द्वारा दोनों याचिकाओं को आईए नंबर 415 और 416 ऑफ 2000 को खारिज कर दिया। प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने सीआरपी संख्या 502 और 505 के तहत उच्च न्यायालय में सिविल रिवीजन दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसे अंततः 18.09.2002 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने 2003 की समीक्षा सीएमपी संख्या 2102 के तहत समीक्षा याचिका दायर की, जिसे 25.06.2003 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादियों ने 2004 की सिविल अपील संख्या 7940 से 7942 में इस न्यायालय में अपील की, जिसे 15.03.2007 को खारिज कर दिया गया।

8. जब प्रतिवादी इस न्यायालय में दावा हार गए और उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, तो आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत एक नई याचिका दायर की गई जिसमें लिखित बयान में संशोधन करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी गई। उक्त आवेदन 2007 के आईए एसआर नंबर 593 के रूप में पंजीकृत किया गया था। विचारण न्यायालय ने एक गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। आदेश

को पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे विचारण न्यायालय को आवेदन पंजीकृत करने और एक तर्कसंगत आदेश पारित करके उसका निपटान करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विचारण न्यायालय ने अंततः संशोधन याचिका पर सुनवाई की और दिनांक 27.09.2007 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति देते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया।

9. वादी-समाज ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने वाले उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। अनुच्छेद 227 के तहत वादी-सोसाइटी द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई की गई और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2007 के आदेश के तहत उन याचिकाओं को अनुमति दी गई और लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसलिए, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें दायर की गईं।

10. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत ए. दवे और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफ़ा ए. अहमदी ने इस प्रस्ताव के लिए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है

और असंगत किया जा सकता है। लिखित बयान में दलील ली जा सकती है. विद्वान वकील ने हमें यह समझाने की भी कोशिश की कि आदेश 6 नियम 16 और आदेश 8 नियम 9 के तहत याचिका पर पारित आदेश सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर बाद के आवेदन पर न्यायिक के रूप में काम नहीं करेगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने कानून के स्थापित सिद्धांत की सही ढंग से सराहना नहीं की है और मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार किए बिना विवादित आदेश पारित कर दिया है।

11. दूसरी ओर, वादी-सोसाइटी (यहाँ प्रतिवादी) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल. नागेश्वर राव ने सबसे पहले तर्क दिया कि संशोधन के लिए आवेदन केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि यह 13 साल बाद दायर किया गया था। मुकदमे की स्थापना और वह भी तब जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और वादी के गवाह से जिरह हो चुकी थी। श्री राव ने तर्क दिया कि विघटनकारी याचिका को लिखित बयान में संशोधन के माध्यम से लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील के अनुसार, लिखित बयान में संशोधन के लिए प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए आधार पर पहले ही आदेश 6 नियम 16 के तहत दायर याचिका और आदेश 8 नियम 9 और आदेश 6 नियम 5 सीपीसी के तहत चर्चा की जा चुकी है। उक्त आवेदनों को निचली

न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इस आदेश की इस न्यायालय ने भी पुष्टि की थी।

12. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने से पहले, हम पहले मुकदमे में प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लिखित बयान को पुन: प्रस्तुत करना चाहेंगे। लिखित बयान में केवल चार पैराग्राफ हैं, जो इस प्रकार हैं:-

> "प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दायर लिखित बयान
>
> 1. प्रथम प्रतिवादी को वादी सोसायटी के निगमन से पहले उसके लिए भूमि खरीदने का कार्य सौंपा गया था। चूंकि सोसायटी के पंजीकरण और निगमन में देरी हुई थी, इसलिए मुकदमे की जमीन पहले प्रतिवादी के नाम पर खरीदी गई थी, जो श्री मोहम्मद सरवर और अन्य के प्रमोटरों में से एक है और पट्टा इन प्रतिवादियों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इन प्रतिवादियों ने वादी के लाभ के लिए इसे अपने पास रखा और 28.8.2001 को सोसायटी के निगमित होने के बाद, वादी को जमीन सौंप दी और 16.9.1981 को एक ज्ञापन भी निष्पादित किया, जिसे वादी सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
>
> 2. ज्ञापन की शर्तों में से एक यह थी कि वादी भूमि के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिवादियों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान

करने के लिए सहमत है। चूंकि वादी ने खातों के निपटान को स्थगित कर दिया था, इसलिए इन प्रतिवादियों ने वादी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं किया।

3. मुकदमा दायर होने के बाद मध्यस्थता और समझौता होता है और रुपये की राशि होती है। इन प्रतिवादियों को 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) का पूरा भुगतान किया जाता है और ये प्रतिवादी वादी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं, जिसने पहले ही वाद में बताए अनुसार स्वामित्व हासिल कर लिया है।

4. इसलिए मुकदमे का फैसला प्रार्थना के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी लागत के।

प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण के लिए वकील 1 से 4

<u>सत्यापन</u>

ऊपर बताए गए तथ्य हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य हैं।''

13. लिखित बयान के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से न केवल वादी के मामले को

स्वीकार किया, बल्कि रुपये की प्राप्ति भी स्वीकार की। 1,00,000/- और वादी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरित करने की उनकी इच्छा। प्रतिवादियों ने, ऐसी स्वीकारोक्ति के आधार पर, न्यायालय से प्रार्थना की कि मुकदमे का फैसला सुनाया जाए, लेकिन बिना किसी लागत के।

14. जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने 28.02.2000 को सीपीसी के आदेश 6 नियम 16 के तहत 2000 के आईए संख्या 415 के तहत आवेदन दायर किया था और प्रार्थना की थी कि पहले लिखित बयान को हटा दिया जाए क्योंकि यह उनके हितों के खिलाफ था। सीपीसी के आदेश 8 नियम 9 के तहत 2000 का IANo.416 नामक एक अन्य आवेदन यह प्रार्थना करते हुए दायर किया गया था कि प्रतिवादियों को मुकदमे में विस्तृत लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि उनके द्वारा दायर पहले लिखित बयान उनके हितों के खिलाफ था। दोनों आवेदनों को विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ लिया गया और सामान्य आदेश दिनांक 04.01.2002 द्वारा निपटाया गया। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दो आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को उस मुकदमे में अपने लिखित बयान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत वादी-समाज के दावे को स्वीकार किया गया था। आवेदनों को खारिज करते समय, विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की और वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया और नए लिखित बयान

दाखिल करके प्रवेश वापस लेने के संबंध में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी विचार किया।

15. इस स्तर पर, हमें यह उल्लेख करना होगा कि वादी-सोसाइटी द्वारा मुकदमा शुरू करने से पहले ही, प्रतिवादियों ने उसी वकील के माध्यम से शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित एक कैविएट दायर की थी जिसमें वादी-सोसाइटी के पूरे दावे को स्वीकार कर लिया गया था। कैविएट में की गई एकमात्र शिकायत यह थी कि समझौते के ज्ञापन के तहत सहमति के अनुसार देय राशि का निपटान किए बिना, वादी-सोसाइटी वाद की भूमि को आवंटित करने और देय राशि का भुगतान किए बिना उसी का निपटान करने की कोशिश कर रही थी। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2002 के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं (पेपर बुक के पृष्ठ 165-170 से):

> "16. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रतिवादियों और अन्य लोगों के बीच पहले के मुकदमे का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादियों के पास वादी समाज के मुकदमे के दावे को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, बल्कि उन कारणों से है कि प्रतिवादियों के साथ दाखिल करने में धोखाधड़ी की गई थी। उनका लिखित बयान. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भीकाजी केशाओ जोशी और अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी और अन्य के फैसले पर भरोसा कर रहे हैं (एआईआर 1955 एससी

610) ने तर्क दिया कि न्यायालय लिखित बयान को हटाने का आदेश दे सकता है और प्रतिवादियों को विशिष्ट दलीलों के साथ प्रतिस्थापित लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। उक्त निर्णय में, उक्त चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के भ्रष्ट आचरण के अस्पष्ट आरोप लगाए और उक्त परिस्थितियों में यह पाया गया कि न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और बेहतर विवरण मांग सकती है। यह याचिकाकर्ताओं - प्रतिवादियों का मामला नहीं है कि उनका लिखित बयान अस्पष्ट है और इसलिए, बेहतर विवरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी ओर से दायर पहले लिखित बयान को हटाया जा सकता है और उन्हें एक विस्तृत प्रतिस्थापित लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। मुकदमे ओएस नंबर 408/94 (इस न्यायालय की फाइल पर 2000 का ओएस 1) में प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान में प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से पूरे मुकदमे के दावे को स्वीकार किया था और आगे उल्लेख किया है कि उन्हें इसके लिए कोई आपत्ति नहीं थी। मुकदमा डिक्री किया जाना है. इसमें कोई संदेह नहीं है, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके वकील श्री सुनील कुमार ने कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए और यह उनके निर्देशों के विपरीत है, उन्होंने वादी-समाज के साथ मिलकर उस

मुकदमे के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने शिकायत की थी। बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश को उक्त वकील के खिलाफ। Ex.B.1 07.07.1994 को वादी समाज के खिलाफ तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट की फाइल पर कैविएट संख्या 178/94 की ज़ेरॉक्स प्रमाणित प्रति है। उक्त कैविएट याचिका में भी, मुकदमे में प्रतिवादियों ने वादी-समाज के पूरे दावे को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस कैविएट के तहत प्रतिवादियों की शिकायत समझौते के ज्ञापन के तहत सहमति के अनुसार देय राशि के निपटान के बिना थी, वादी समाज कोशिश कर रहा था वाद भूमि को आवंटित करने और उसकी राशि का भुगतान किए बिना उसका निपटान करने के लिए, और इसलिए, यदि उक्त संपत्ति के संबंध में उसके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा मुकदमा दायर किया जाता है, तो उसे नोटिस दिया जा सकता है। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त कैविएट याचिका में प्रतिवादियों की कथित स्वीकारोक्ति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वास्तव में, प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में यह दलील दी गई थी कि मुकदमा दायर होने के बाद मध्यस्थता और रुपये की राशि दी गई थी। निपटान हेतु उन्हें 1,00,000/- का भुगतान किया गया।

17. प्रथम प्रतिवादी-वादी सोसायटी के विद्वान वकील ने *मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया। एम/एस लाधा राम एंड कंपनी (एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 680), बीके नारायण पिल्लई और परमेश्वरन पिल्लई और अन्य (2000)* 1 सुप्रीम कोर्ट केस 712) और *हीरालाल और कल्याण मलंद और अन्य (1998) 1* सुप्रीम कोर्ट केस 278) ने तर्क दिया कि कोई भी संशोधन जो पूरी तरह से अलग नया मामला पेश करता है और लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से प्राप्त लाभ को वादी को विस्थापित करने की मांग करता है, स्वीकार्य नहीं है। *मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम एम/एस लाधा राम एंड कंपनी* (एआईआर 1988 सुप्रीम कोर्ट 680) के फैसले में एक संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी एक पूरी तरह से अलग मामला पेश करना चाहता था। तथ्यों और उक्त परिस्थितियों में, यह माना गया कि प्रतिवादियों को उनके लिखित बयान में दिए गए मामले को पूरी तरह से बदलने और एक पूरी तरह से अलग नए मामले को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसे संशोधनों की अनुमति दी जाती है तो वादी को अपरिवर्तनीय रूप से पूर्वाग्रहित किया जाएगा। प्रतिवादियों से स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के अवसर से इनकार कर

दिया। *हीरालाल बनाम कायलान मल और अन्य* (1998) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 278, और *हीरालाल बनाम कायलान मल और अन्य* (एआईआर 1998 सुप्रीम कोर्ट 618) में यह माना गया कि एक बार जब लिखित बयान में वादी के पक्ष में स्वीकारोक्ति शामिल हो जाती है, तो प्रतिवादियों के ऐसे स्वीकारोक्ति के संशोधन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह की वापसी वादी के मामले को पूरी तरह से विस्थापित करने के बराबर होगी, जिसके कारण वह अपूरणीय पूर्वाग्रह है. बीके नारायण पिल्लई और परमेश्वरन पिल्लई और अन्य (2000) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 712 में, यह माना गया था कि हालांकि प्रतिवादी को संशोधन के माध्यम से बचाव में वैकल्पिक दलीलें लेने का अधिकार है, यह योग्यता के अधीन होगा कि (i) प्रस्तावित संशोधन दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए; (ii) वादी के पक्ष में की गई कोई भी स्वीकृति वापस नहीं ली जानी चाहिए; और (iii) असंगत और विरोधाभासी आरोप जो स्वीकृत तथ्यों को नकारते हैं, नहीं उठाए जाने चाहिए। वर्तमान याचिकाओं के तहत, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी वादी समाज के मुकदमे के दावे के संबंध में उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को छीनने का इरादा रखते हैं। कानून यह है कि कोई भी अतिरिक्त लिखित बयान पूरी तरह से नया मामला स्थापित नहीं

करना चाहिए या ऐसे तथ्यों को नहीं बताना चाहिए जो मूल लिखित बयान से सीधे भिन्न हों ताकि मामले में मुद्दा पूरी तरह से बदल जाए। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादी वैकल्पिक दलीलें लेने का इरादा रखते हैं या वे अपने लिखित बयान में उनके द्वारा की गई अस्पष्ट दलीलों को समझाने का इरादा रखते हैं। यह भी अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की याचिका नहीं है, बल्कि वादी समाज के पक्ष में की गई स्वीकारोक्ति से उबरने के लिए मूल लिखित बयान को प्रतिस्थापित करने की याचिका है। उनके हलफनामे को साबित करने के लिए न्यायालय के सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, दाखिल किए गए दस्तावेज़ याचिकाकर्ता के पिछले वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उसके हलफनामे का समर्थन करने में सहायक नहीं हैं, ताकि न्यायालय से अनुरोध किया जा सके कि उन्हें अपने पहले लिखे गए बयान के स्थान पर एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए। बयान जिसमें उन्होंने वादी समाज के पूरे दावे को स्वीकार किया था। लिखित बयान के अवलोकन से, जिसे पहले लिखित बयान के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है, पता चलता है कि प्रतिवादी लिखित बयान में उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के

खिलाफ एक नया मामला पेश करते हैं। शीर्ष न्यायालय के स्थापित कानून के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को न्यायालय से यह अनुरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके द्वारा दायर पहले के लिखित बयान को हटा दिया जाए या उनके द्वारा लिखित में की गई स्वीकारोक्ति के विपरीत उन्हें एक नया लिखित बयान देने की अनुमति दी जाए।

18. निस्संदेह, याचिकाकर्ता ने उक्त अधिवक्ता और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दायर की थी और उन आपराधिक कार्यवाही की प्रतियां इस याचिका में दायर की गई हैं। माना कि उक्त आपराधिक मामला लंबित है। इसके अलावा, यह IA 2217/95 दाखिल करने के बाद था। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल न्यायालयों के निर्णय आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं और इसका विपरीत सत्य नहीं है (करमचंद बनाम भारत संघ (एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 1244) में निर्णय के अनुसार)। वादी समाज नहीं है पिछली सिविल कार्यवाही का एक पक्ष, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका में दायर किया गया है। इसलिए, वे दस्तावेज़, जो याचिकाकर्ताओं - प्रतिवादियों की ओर से दायर किए गए हैं, पहले प्रतिवादी - वादी समाज पर बाध्यकारी नहीं हैं। राजस्व रिकॉर्ड दायर की गई याचिकाएं भी इस याचिका में उनके तर्क के

समर्थन में याचिकाकर्ताओं के लिए सहायक नहीं हैं। क्या समझौते की तारीख तक मुख्य प्रमोटर नाबालिग था जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है, यह भी इस याचिका के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय मानती है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर किए गए दस्तावेज़ याचिकाओं के दावे को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उपरोक्त कारणों से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों को अनुमति नहीं दी जा सकती है मुकदमे में उनके द्वारा दायर किए गए पहले के लिखित बयान को प्रतिस्थापित करें, जिसके तहत विरोधाभासी दलीलों को लेकर एक पूरी तरह से नए लिखित बयान के माध्यम से वादी समाज के मुकदमे के दावे को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार यह न्यायालय याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाती है।

19. परिणामस्वरूप, याचिकाएँ बिना किसी लागत के खारिज कर दी जाती हैं।

16. विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, आदेश 8 नियम 9 और आदेश 6 नियम 16 सीपीसी के तहत प्रतिवादियों की दो याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी गईं कि प्रतिवादियों को

पहले लिखित बयान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें स्वीकारोक्ति थी वादी-सोसाइटी का मुकदमा दावा।

17. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि यद्यपि कुछ स्वीकारोक्ति लिखित बयान में की गई थी, लेकिन उसे नया विस्तृत लिखित बयान दाखिल करके वापस लिया जा सकता है। उक्त पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2002 (पेपरबुक के पृष्ठ 184 से 186) में कहा:-

> "निचली न्यायालय ने इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की थी, मैं इस पहलू पर नीचे की न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत हूं और मेरा मानना है कि वे सही और वैध हैं।
>
> निचली न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने भीकाजी केशाओ जोशी और अन्य बनाम बृजलाल नदंलाल बियानी और अन्य (एआईआर 1955 एससी 610) में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि न्यायालय लिखित बयान को हटाने का आदेश दे सकती है और प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित फाइल करने की अनुमति दे सकती है। विशिष्ट दलीलों के साथ लिखित बयान।

निचली न्यायालय ने इसे सही ढंग से अलग किया और माना कि यह लागू नहीं है।

निचली अपीलीय न्यायालय ने आई.ए.एस. को खारिज करते हुए। हीरालाल बनाम कायलान मल और अन्य (एआईआर 1998 एससी 618) में रिपोर्ट किए गए शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया था कि एक बार लिखित बयान में वादी के पक्ष में स्वीकारोक्ति शामिल है, तो प्रतिवादियों के ऐसे स्वीकारोक्ति में संशोधन किया जाएगा । वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस तरह की वापसी वादी के मामले को पूरी तरह से विस्थापित करने के समान होगी जिससे उसे अपूरणीय पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। *बीके नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई और अन्य* (2000 (1) एससीसी 712) में निचली न्यायालय द्वारा संदर्भित सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में यह माना गया था कि हालांकि प्रतिवादी को बचाव में वैकल्पिक दलीलें लेने का अधिकार है। संशोधन, यह उन योग्यताओं के अधीन होगा जो हैं (1) प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और (2) वादी के पक्ष में की गई कोई भी स्वीकारोक्ति वापस नहीं ली जानी चाहिए और (3) असंगत

और विरोधाभासी आरोप जो अस्वीकार करते हैं स्वीकृत तथ्यों को नहीं उठाया जाना चाहिए।

मौजूदा मामले में अब सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में की गई स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है और शीर्ष न्यायालय की भाषा में जवाब 'अनुमति योग्य नहीं' है।

जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति पहले प्रतिवादी द्वारा उसकी कैविएट याचिका पर दायर हलफनामे में अपनाए गए मूल रुख और दलीलों से बिल्कुल मेल खाती है और उठाया गया एकमात्र विवाद प्रतिवादी को पैसे के भुगतान के संबंध में है। . ऐसे मामले में, मेरा दृढ़ मत है कि प्रतिवादी ने वर्तमान आईए दाखिल करने में साफ हाथों से न्यायालय का रुख नहीं किया था।

यह भी ध्यान रखना होगा कि वकील के खिलाफ लगाए गए आरोप अब तक स्थापित नहीं हुए हैं। वर्तमान जैसी परिस्थितियों में पुलिस के समक्ष या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष शिकायत दर्ज करना केवल वकील के पेशे की शालीनता और गरिमा को खतरे में डालेगा। वकील के खिलाफ बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाने के इस रवैये को हर तरह से रोकना होगा।

हालाँकि, इस अवलोकन को उक्त वकील के खिलाफ पहले से ही शुरू की गई और लंबित कार्यवाही पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं समझा जाएगा। दूसरे तरीके से कहें तो, प्रतिवादी का मूल रुख, जैसा कि कैविएट याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है, वर्तमान आईए दाखिल करने के आधार को ही ध्वस्त या काट देता है। मेरा यह भी मानना है कि यदि इस प्रकार के आरोप बिना प्रमाणित किए लगाए जाते हैं और यदि उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां झूठे मामलों वाले वादी वास्तविक या निर्दोष अधिवक्ताओं के करियर को खराब करने का सहारा लेंगे। प्रतिवादी का आचरण स्पष्ट रूप से शरारतपूर्ण है और यह न्यायालय प्रतिवादी जैसे वादी को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे सकती है, जो गंदे हाथों से न्यायालय में आया है।

इस न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि एक अन्य मुकदमे में, जो वर्तमान मुकदमे से जुड़ा नहीं है, प्रतिवादी ने एक अन्य वकील के खिलाफ इसी तरह के आरोपों का सहारा लिया और निश्चित रूप से विचारण न्यायालय ने उन आरोपों पर विचार नहीं किया।

निचली न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और आई.ए.एस. को खारिज कर दिया। ठोस और ठोस कारणों के साथ और मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं मिला। तदनुसार, मैं निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं।

पुनरीक्षण याचिकाएँ जुर्माने सहित ख़ारिज की जाती हैं।"

18. विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां मुख्य रूप से इस कारण से उद्धृत किए गए हैं कि आदेश 8 नियम 9 और आदेश 6 नियम 16 के तहत याचिकाओं पर विचार करते समय दोनों न्यायालयें इस प्रश्न पर भी विचार कर रही हैं: क्या प्रतिवादियों को नया लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देकर या पहले लिखित बयान को हटाकर उन स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है।

19. उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने 2004 की सिविल अपील संख्या 7940-7942 में इस न्यायालय का रुख किया। कोई योग्यता न पाए जाने पर, इस न्यायालय ने दिनांक 15.03.2007 के आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया।

20. मुकदमे में भाग लेने के बजाय, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने लिखित बयान में संशोधन की मांग करते हुए आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत एक और याचिका दायर की। उक्त संशोधन याचिका को विचारण

न्यायालय ने अनुमति दे दी थी और उसके खिलाफ वादी-समाज ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.12.2007 को आक्षेपित आदेश पारित करके पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

> "15. *संयुक्त प्रांत विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड* में अनुपात। मामला (एआईआर 1972 एससी 1201) कि रिमांड के आदेश में दिए गए किसी विशेष बिंदु पर निर्णय रिमांड के बाद पारित अंतिम आदेश के खिलाफ दायर अपील में न्यायिक के रूप में काम नहीं करता है; इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि इस मामले में कोई 'रिमांड का आदेश' नहीं है क्योंकि वादी प्रतिवादियों द्वारा किए गए आवेदनों का विरोध करने के लिए 'रिमांड के आदेश' में किसी भी टिप्पणी पर भरोसा नहीं कर रहा है।
>
> 16. *सत्यध्यान घोषाल* केस (एआईआर 1960 एससी 941), *अर्जुन सिंह* केस (एआईआर 1964 एससी 993) और *संयुक्त प्रांत विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड* में अनुपात को देखते हुए। मामले (..सुप्रा) में एक ही राहत के लिए लगातार आवेदनों की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में खारिज भी किया जा सकता है।

17. प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 2000 की आईए संख्या 416 दाखिल करने के बाद, प्रतिवादियों को एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि उनकी ओर से दायर लिखित बयान उसी टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। जिस पर वाद पत्र टाइप किया गया था। इन संशोधनों में चुनौती दिए गए सामान्य आदेश में, विचारण न्यायालय ने उस विवाद पर विचार किया और माना कि उस विवाद का निर्णय विचारणके समय किया जाना है, लेकिन इस स्तर पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर उस निष्कर्ष को ग़लत नहीं कहा जा सकता।

18. जैसा कि वादी के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया था, विचारण न्यायालय, जो वादी के इस तर्क से सहमत था कि प्रतिवादी धोखाधड़ी की दलील देकर मांगे गए संशोधन की मांग नहीं कर सकते, याचिकाओं को केवल टिप्पणियों के आधार पर अनुमति दी गई थी। *उदय शंकर त्रियार बनाम राम कलेवर प्रसाद सिंह* एआईआर 2006 एससी 269. उसी फैसले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया, जो न्याय के लिए एक हाथ है, को कभी भी न्याय दिलाने या किसी दमनकारी या दंडात्मक उपयोग द्वारा अन्याय को कायम रखने का उपकरण नहीं बनाया

जाना चाहिए। . विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि प्रतिवादी एक ही राहत के लिए बार-बार याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, जिसे पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देकर एक अलग रूप में खारिज कर दिया गया था, ने याचिकाओं को अनुमति देना उचित समझा और इस तरह वस्तुतः शून्य कर दिया। 2000 के IANos.415 और 416 की बर्खास्तगी का आदेश पहले पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी की थी।

21. मामले के गुण-दोष पर जाने से पहले, हम दो प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे। आदेश 6 नियम 16 और आदेश 6 नियम 17 सीपीसी जो तत्काल मामले में शामिल हैं। ये दो प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"16. अभिवचनों को ख़त्म करना-न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अभिवचन में किसी भी मामले को निरस्त करने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है-

(ए) जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या कष्टप्रद हो सकता है, या

(बी) जो पूर्वाग्रह, शर्मिंदगी या मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में देरी कर सकता है, या

(सी) जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।]

17. अभिवचनों में संशोधन - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपने अभिवचनों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो उचित हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं पक्षकारों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करना।

बशर्ते कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकता था।

22. आदेश 6 नियम 16 सीपीसी को सीपीसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह प्रावधान संशोधन या दलीलों को खारिज करने से संबंधित है, जो एक पार्टी अपने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों में करना चाहती है। दूसरे शब्दों में, वादी या प्रतिवादी न्यायालय से अपने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों को इस आधार पर खारिज करने के लिए कह सकता है कि दलीलें अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या कष्टप्रद दिखाई गई हैं। यह नियम एक्स डेबिटो जस्टिसिया के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के तहत न्यायालय को दलीलों में से किसी भी मामले को खारिज करने का अधिकार है जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या कष्टप्रद प्रतीत होता है या जो मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में पूर्वाग्रह, शर्मिंदगी या देरी करता है।

23. दूसरी ओर, आदेश 6 नियम 17 सीपीसी न्यायालय को किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने का अधिकार देता है और ऐसे आवेदन पर न्यायालय उक्त नियम में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन पक्षकारों को अपनी दलीलों में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है।

24. हालाँकि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने आदेश 6 नियम 16 सीपीसी के तहत याचिका को लेबल करते हुए, अपनी स्वयं की दलील यानी लिखित बयान को हटाने के लिए याचिका दायर की, लेकिन वास्तव में आवेदन को आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत निपटाया गया था। विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर चर्चा की और प्रतिवादियों को उस लिखित बयान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जिसके तहत वादी-समाज के मुकदमे के दावे को स्वीकार किया गया था। यहां ऊपर उद्धृत आदेश के प्रासंगिक भाग से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को मुकदमे में दायर अपने पहले लिखित बयान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके तहत वादी-समाज के दावे को स्वीकार किया गया था। (यहां प्रतिवादी)। इसी प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित सभी निर्णयों पर विचार किया कि क्या प्रतिवादी लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति को वापस ले सकते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर

पहुंचे कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता ऐसा नहीं कर सकते। आदेश 8 नियम 9 या आदेश 6 नियम 16 सीपीसी का सहारा लेकर नए लिखित बयान दाखिल करने की मांग करके लिखित बयान में की गई स्वीकारोक्ति से मुकरने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त परिसर में, लगभग 13 वर्षों के बाद आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रतिवादियों द्वारा एक नई याचिका दायर करना, जब मुकदमे की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी, पूरी तरह से गलत धारणा है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सही कहा है कि एक ही राहत के लिए बाद में आवेदन दाखिल करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत एक बाद की याचिका में प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई राहत को प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा आदेश 6 नियम 16 और आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के तहत दायर की गई दो पिछली याचिकाओं पर विस्तृत रूप से निपटाया गया था और इसलिए, आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत याचिका को लेबल करने वाले प्रतिवादियों द्वारा दायर बाद की याचिका पूरी तरह से गलत है और विचार करने योग्य नहीं है।

25. मामले पर अपना पूरा विचार करने के बाद, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली। इसलिए, इन अपीलों में कोई दम नहीं है और इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री विकास राम चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****